NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं सामाजिक समानता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. उषा लहरे
अतिथि व्याख्याता (समाजशास्त्र)
शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, कोरबा (छत्तीसगढ़)

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी नीति है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, बहुभाषिक, लचीला एवं समान अवसर आधारित बनाना है। यह नीति केवल शैक्षिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता एवं सतत विकास की अवधारणा को भी सशक्त बनाने का प्रयास करती है। वर्तमान अध्ययन में शिक्षा एवं सामाजिक समानता के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता, जातीय विभाजन, आर्थिक विषमता, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन एवं ग्रामीण-शहरी अंतर शिक्षा व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहे हैं। समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण सामाजिक गतिशीलता एवं समान अवसर की अवधारणा प्रभावित होती है। नई शिक्षा नीति 2020 इन असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा, समान अवसर, मातृभाषा आधारित शिक्षण, डिजिटल शिक्षा, कौशल आधारित अधिगम, बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीकी एकीकरण पर विशेष बल देती है। नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नीति शिक्षा को केवल रोजगार का माध्यम न मानकर सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक संरक्षण एवं राष्ट्रीय विकास का आधार मानती है। प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के माध्यम से शिक्षा एवं सामाजिक समानता के संबंध का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता एवं समावेशी विकास स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, किन्तु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, डिजिटल अवसंरचना, प्रशासनिक दक्षता एवं सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होगी।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सामाजिक समानता, समावेशी शिक्षा, समाजशास्त्र, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक न्याय, बहुभाषिक शिक्षा।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज के विकास, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय का आधार मानी जाती है। यह न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास का माध्यम है, बल्कि उसके सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में सामाजिक चेतना, नागरिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक मूल्य एवं मानवीय संवेदनाओं का विकास होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को समाज के मूल्यों, मानदंडों एवं सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराती है। यही कारण है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं सामाजिक संरचना का स्तर उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता एवं समावेशिता पर निर्भर करता है। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का माध्यम बनकर व्यक्ति को अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है तथा समाज में समानता एवं न्याय की स्थापना में सहायक होती है।

भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण समाज है, जहाँ जाति, वर्ग, लिंग, भाषा, धर्म एवं क्षेत्रीय असमानताएँ लंबे समय से विद्यमान रही हैं। इन सामाजिक असमानताओं का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, निजी एवं शासकीय विद्यालयों, आर्थिक रूप से संपन्न एवं वंचित वर्गों तथा पुरुष एवं महिला विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक अवसरों में व्यापक अंतर पाया जाता है। आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है, जिसके कारण सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल युग में तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता ने "डिजिटल विभाजन" जैसी नई सामाजिक समस्या को जन्म दिया है, जिसने शिक्षा में असमानता को और अधिक बढ़ाया है।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु एक नवीन, व्यापक एवं दूरदर्शी नीति के रूप में प्रस्तुत की गई। यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुभाषिक, कौशल-आधारित एवं रोजगारोन्मुख बनाने पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जो प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि से परे समान अवसर प्रदान कर सके। नीति में विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के लिए शिक्षा की पहुँच, गुणवत्ता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत मातृभाषा आधारित शिक्षण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल अधिगम, समावेशी शिक्षा एवं बहुविषयक अध्ययन जैसी अवधारणाओं को विशेष महत्व दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन या रोजगार प्राप्ति का साधन नहीं मानती, बल्कि इसे सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण माध्यम मानती है। यह नीति शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में कार्य करते हुए प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह नीति सामाजिक परिवर्तन एवं समावेशी विकास की अवधारणा को सुदृढ़ करने वाली नीति के रूप में उभरती है। प्रस्तुत अध्ययन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि यह नीति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता स्थापित करने में किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

अध्ययन का सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख माध्यम है। एमिल दुर्खीम के अनुसार शिक्षा समाज के नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक एकता को बनाए रखने का साधन है। वहीं कार्ल मार्क्स ने शिक्षा को वर्गीय असमानताओं को बनाए रखने वाला उपकरण माना। पियरे बोरदियो ने सांस्कृतिक पूँजी के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि समाज के उच्च वर्ग शिक्षा के माध्यम से अपने प्रभुत्व को बनाए रखते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह नीति शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन एवं समावेशी विकास का आधार मानती है। इसमें बहुभाषिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं समावेशी अधिगम के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक असमानता एक गंभीर एवं बहुआयामी समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है। भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय विषमताएँ लंबे समय से विद्यमान रही हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर देखा जा सकता

है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी आज भी गुणवत्तापूर्ण एवं समान शिक्षा के अवसरों से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। निजी एवं शासकीय शिक्षण संस्थाओं के बीच संसाधनों, अधिगम सुविधाओं एवं शिक्षण गुणवत्ता में व्यापक अंतर पाया जाता है, जिसके कारण सामाजिक असमानता और अधिक गहरी होती जा रही है। शिक्षा में यह असमानता केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रोजगार, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक उन्नति एवं जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा में असमानता सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक बहिष्करण को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक न्याय एवं समान अवसर की अवधारणा प्रभावित होती है।

वर्तमान डिजिटल युग में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी संसाधनों का महत्व तेजी से बढ़ा है। ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एवं डिजिटल सामग्री ने शिक्षा के नए आयाम विकसित किए हैं, किन्तु इसके साथ ही "डिजिटल विभाजन" की समस्या भी उभरकर सामने आई है। समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल संसाधनों से वंचित है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण शैक्षिक अवसरों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह समस्या और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई, जब अनेक विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने में असमर्थ रहे। इस प्रकार डिजिटल शिक्षा के विस्तार ने जहाँ एक ओर शिक्षा की पहुँच को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर नई सामाजिक एवं शैक्षिक असमानताओं को भी जन्म दिया है।

ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह नीति शिक्षा को अधिक समावेशी, समान अवसर आधारित एवं सामाजिक न्यायोन्मुख बनाने का प्रयास करती है। नीति में विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs) के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। मातृभाषा आधारित शिक्षण, बहुभाषिक शिक्षा, समावेशी अधिगम, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा जैसे प्रावधान सामाजिक समानता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सामाजिक प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास करेगा कि यह नीति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करने में किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।

यह अध्ययन नीति की सामाजिक उपयोगिता, समावेशी दृष्टिकोण, व्यावहारिक चुनौतियों एवं क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं को समझने में भी सहायक होगा। इसके अतिरिक्त यह शोध शिक्षकों, शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं एवं शोधार्थियों को शिक्षा एवं सामाजिक समानता के मध्य संबंध को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करेगा। प्रस्तुत अध्ययन भविष्य में शिक्षा सुधार, समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों के निर्माण में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

समस्या कथन

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं सामाजिक समानता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण"

अध्ययन के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
2. शिक्षा एवं सामाजिक समानता के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।
3. NEP 2020 के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं समावेशी शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।
4. शिक्षा में विद्यमान सामाजिक असमानताओं का विश्लेषण करना।
5. NEP 2020 के क्रियान्वयन की चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है?
2. क्या NEP 2020 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए लाभकारी है?
3. क्या डिजिटल शिक्षा सामाजिक समानता को प्रभावित करती है?
4. क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक असमानता विद्यमान है?

परिकल्पना

- **H_0:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में सामाजिक समानता स्थापित करने में प्रभावी नहीं है।
- **H_1:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में सामाजिक समानता स्थापित करने में प्रभावी है।

साहित्य समीक्षा

- **कुमार (2021)** द्वारा किए गए अध्ययन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह समझना था कि नई शिक्षा नीति सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों को किस प्रकार मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती है। शोध में पाया गया कि NEP 2020 ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराती है। नीति में मातृभाषा आधारित शिक्षण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, डिजिटल अधिगम एवं बहुविषयक शिक्षा जैसी अवधारणाएँ विद्यार्थियों की सहभागिता एवं अधिगम स्तर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तो यह शिक्षा में सामाजिक समानता एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **शर्मा (2022)** के अध्ययन में डिजिटल शिक्षा एवं सामाजिक असमानता के मध्य संबंध का विश्लेषण किया गया। शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि आधुनिक तकनीकी संसाधनों के विस्तार ने शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया कि ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एवं डिजिटल संसाधनों के कारण शिक्षा की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सकी। किन्तु शोध में यह भी पाया गया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण वर्गों के विद्यार्थियों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन एवं कंप्यूटर जैसी सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण "डिजिटल विभाजन" की समस्या उत्पन्न हो रही है। अध्ययन के अनुसार डिजिटल शिक्षा ने नई संभावनाएँ तो विकसित की हैं, परंतु इसके साथ नई सामाजिक एवं शैक्षिक असमानताएँ भी उभरकर सामने आई हैं।
- **यूनेस्को (2021)** की रिपोर्ट में समावेशी शिक्षा को सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय एवं सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। अध्ययन में यह उल्लेख किया गया कि समावेशी शिक्षा केवल विद्यालयों में प्रवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अधिगम की गुणवत्ता एवं सामाजिक स्वीकार्यता से भी संबंधित है। रिपोर्ट में विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों, अल्पसंख्यकों एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। यूनेस्को ने यह भी स्पष्ट किया कि समावेशी एवं समान अवसर आधारित शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **सिंह (2023)** द्वारा किए गए अध्ययन में बहुभाषिक शिक्षा एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक सहभागिता के मध्य संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। अध्ययन में यह पाया गया कि मातृभाषा एवं स्थानीय भाषाओं में शिक्षण विद्यार्थियों की समझ, अभिव्यक्ति क्षमता एवं अधिगम स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। शोध के अनुसार बहुभाषिक शिक्षा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सहभागिता एवं सांस्कृतिक जुड़ाव

को मजबूत करती है। विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को अधिक प्रभावी बनाता है। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषिक शिक्षा को दिया गया महत्व शिक्षा को अधिक समावेशी एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

- **एनसीईआरटी (2022)** की रिपोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके शैक्षिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि NEP 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अध्ययन के अनुसार यह नीति शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी, कौशल-आधारित एवं समान अवसर आधारित बनाने का प्रयास करती है। रिपोर्ट में विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं बहुविषयक अधिगम जैसी अवधारणाओं को शिक्षा सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं समानता स्थापित करने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

शोध अंतराल

उपलब्ध अध्ययनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शैक्षिक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है, किन्तु सामाजिक समानता एवं समाजशास्त्रीय विश्लेषण के संदर्भ में सीमित अध्ययन उपलब्ध हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों पर इसके प्रभाव का गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन अपेक्षित है।

शोध पद्धति

- **शोध डिज़ाइन**- प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध डिज़ाइन का प्रयोग किया गया। इस शोध डिज़ाइन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षा एवं सामाजिक समानता से संबंधित विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक एवं संरचनात्मक पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया। वर्णनात्मक शोध के माध्यम से अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किया गया, जबकि विश्लेषणात्मक शोध के माध्यम से शिक्षा एवं सामाजिक समानता के मध्य संबंधों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया।
- **शोध की प्रकृति**- प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की शोध प्रकृति पर आधारित रहा। गुणात्मक शोध पद्धति के माध्यम से उत्तरदाताओं के विचारों, अनुभवों एवं सामाजिक दृष्टिकोणों का अध्ययन किया गया, जबकि मात्रात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत संकलित आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किए गए। इस प्रकार मिश्रित शोध दृष्टिकोण ने अध्ययन को अधिक विश्वसनीय एवं व्यापक बनाया।
- **जनसंख्या**- अध्ययन की जनसंख्या में उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा से संबंधित शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया। अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित उत्तरदाताओं को शामिल कर शिक्षा एवं सामाजिक समानता के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया।
- **न्यादर्श**- प्रस्तुत अध्ययन हेतु कुल 200 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इन उत्तरदाताओं में शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षाविद् सम्मिलित थे, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं सामाजिक समानता के प्रति दृष्टिकोणों का अध्ययन किया गया।
- **न्यादर्श चयन विधि**- अध्ययन में स्तरीकृत एवं उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श चयन विधि का प्रयोग किया गया। स्तरीकृत न्यादर्श चयन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, जबकि उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श चयन के अंतर्गत ऐसे उत्तरदाताओं का चयन किया गया जो अध्ययन विषय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे।
- **आँकड़ों के स्रोत**

- **प्राथमिक स्रोत**- प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं अवलोकन विधियों के माध्यम से किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से उत्तरदाताओं के विचार एवं प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की गईं, जबकि साक्षात्कार के माध्यम से विषय से संबंधित गहन जानकारी एकत्रित की गई। अवलोकन विधि के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था एवं सामाजिक समानता से संबंधित व्यवहारिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया।
- **द्वितीयक स्रोत**- द्वितीयक आँकड़ों के अंतर्गत पुस्तकों, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित दस्तावेजों, विभिन्न जर्नलों एवं विश्वसनीय वेबसाइटों का उपयोग किया गया। इन स्रोतों के माध्यम से अध्ययन विषय की सैद्धांतिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ बनाया गया।

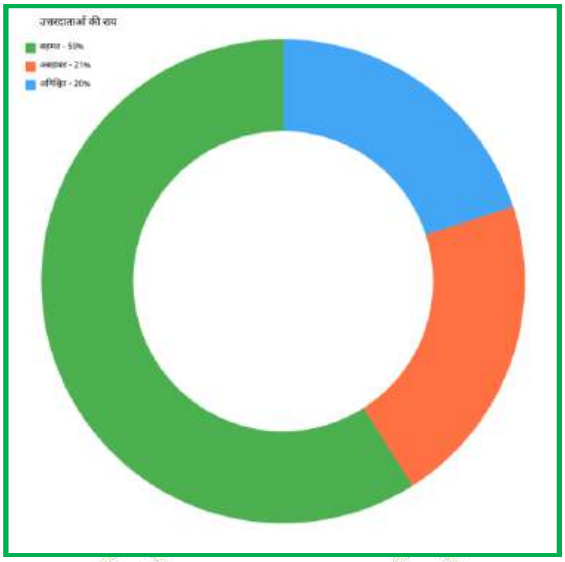
- **शोध उपकरण**- प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के संग्रह हेतु संरचित प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची एवं सामाजिक समानता मापन स्केल का प्रयोग किया गया। संरचित प्रश्नावली के माध्यम से उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं का व्यवस्थित संकलन किया गया, जबकि साक्षात्कार अनुसूची द्वारा गहन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। सामाजिक समानता मापन स्केल के माध्यम से शिक्षा एवं सामाजिक समानता से संबंधित दृष्टिकोणों एवं अनुभवों का मूल्यांकन किया गया।
- **आँकड़ों का संग्रह**- प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों का संग्रह प्रत्यक्ष संपर्क, ऑनलाइन प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि के माध्यम से किया गया। उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई तथा ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों के उत्तरदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई।
- **सांख्यिकीय विश्लेषण**- संकलित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु Mean, Percentage, Standard Deviation एवं t-test जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया। Mean के माध्यम से औसत प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया, Percentage द्वारा विभिन्न प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया तथा Standard Deviation के माध्यम से आँकड़ों के विचलन का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त t-test के माध्यम से विभिन्न समूहों के मध्य प्राप्त अंतर की सार्थकता का परीक्षण किया गया।

सारणी एवं व्याख्या

सारणी 1

शिक्षा में समान अवसर के संबंध में उत्तरदाताओं की राय

राय	संख्या	प्रतिशत
सहमत	118	59%
असहमत	42	21%
अनिश्चित	40	20%



व्याख्या

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शिक्षा में समान अवसर के संबंध में अधिकांश उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा। कुल 200 उत्तरदाताओं में से 118 उत्तरदाताओं अर्थात् 59 प्रतिशत ने इस बात से सहमति व्यक्त की कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन उत्तरदाताओं का मानना था कि नई शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा, मातृभाषा आधारित शिक्षण, डिजिटल अधिगम, बहुविषयक शिक्षा एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ एवं समान अवसर आधारित बनाने का प्रयास किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिल सकती है। वहीं 42 उत्तरदाताओं अर्थात् 21 प्रतिशत ने इस कथन से असहमति व्यक्त की। इन उत्तरदाताओं का मत था कि शिक्षा व्यवस्था में अभी भी अनेक सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ विद्यमान हैं, जिनके कारण सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों की असमान उपलब्धता, निजी एवं शासकीय विद्यालयों की गुणवत्ता में अंतर, डिजिटल संसाधनों की कमी तथा आर्थिक विषमता जैसी समस्याएँ शिक्षा में समानता की राह में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन उत्तरदाताओं के अनुसार केवल नीति निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं संसाधनों की समान उपलब्धता भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 40 उत्तरदाताओं अर्थात् 20 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनिश्चित पाए गए। इन उत्तरदाताओं का मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी प्रारंभिक क्रियान्वयन की अवस्था में है, इसलिए इसके वास्तविक प्रभावों का पूर्ण मूल्यांकन करना शीघ्रता होगी। कुछ उत्तरदाता नीति के प्रावधानों से पूर्णतः परिचित नहीं थे, जबकि कुछ का मत था कि नीति की सफलता उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर करेगी।

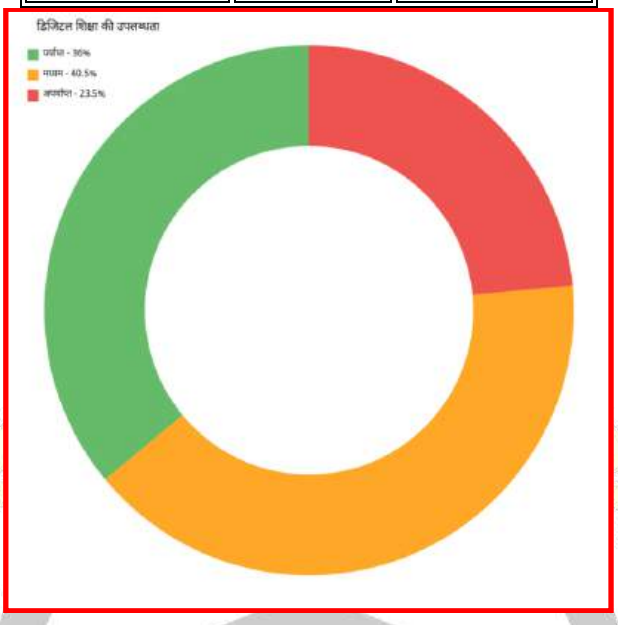
समग्र रूप से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश उत्तरदाता शिक्षा में समान अवसर की अवधारणा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सामाजिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानते हैं। तथापि अध्ययन यह भी संकेत करता है कि शिक्षा में वास्तविक समानता स्थापित करने हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी असमानताओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक होगा।

सारणी 2

डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता

स्थिति	संख्या	प्रतिशत
पर्याप्त	72	36%

स्थिति	संख्या	प्रतिशत
मध्यम	81	40.5%
अपर्याप्त	47	23.5%



व्याख्या

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के अनुसार डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता का स्तर मिश्रित स्थिति में पाया गया। कुल 200 उत्तरदाताओं में से 72 उत्तरदाताओं अर्थात् 36 प्रतिशत ने डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता को पर्याप्त माना। इन उत्तरदाताओं का मत था कि वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन एवं इंटरनेट आधारित शिक्षण संसाधनों के विस्तार ने शिक्षा की पहुँच को अधिक व्यापक बनाया है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों एवं संसाधन सम्पन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनी है। इन उत्तरदाताओं ने यह भी माना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है।

वहीं 81 उत्तरदाताओं अर्थात् 40.5 प्रतिशत ने डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता को मध्यम स्तर का माना। इन उत्तरदाताओं का मानना था कि डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ तो उपलब्ध हैं, किन्तु उनका लाभ सभी विद्यार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट की धीमी गति, तकनीकी संसाधनों की सीमित उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव तथा विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता की कमी जैसी समस्याएँ डिजिटल शिक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। इन उत्तरदाताओं के अनुसार डिजिटल शिक्षा का विस्तार हुआ है, परंतु इसकी गुणवत्ता एवं पहुँच में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त 47 उत्तरदाताओं अर्थात् 23.5 प्रतिशत ने डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता को अपर्याप्त माना। इन उत्तरदाताओं का मत था कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल संसाधनों की कमी विद्यमान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अनेक विद्यार्थी तकनीकी सुविधाओं के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाते हैं। इससे शिक्षा में "डिजिटल विभाजन" की स्थिति उत्पन्न होती है, जो सामाजिक एवं शैक्षिक असमानता को और अधिक बढ़ाती है। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी माना कि डिजिटल शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु तकनीकी अवसंरचना एवं विद्युत व्यवस्था की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, जिसकी कमी कई क्षेत्रों में देखी जाती है।

समग्र रूप से अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि डिजिटल शिक्षा ने शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक एवं सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किन्तु इसकी समान एवं प्रभावी उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। डिजिटल शिक्षा को वास्तव में समावेशी एवं समान अवसर आधारित बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों का विस्तार, इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक होगा।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, समान अवसर आधारित एवं सामाजिक न्यायोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि नीति में समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे शिक्षा की पहुँच एवं सहभागिता को बढ़ावा मिल सके। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि डिजिटल शिक्षा के विस्तार के बावजूद "डिजिटल विभाजन" की समस्या अभी भी विद्यमान है, जो सामाजिक समानता एवं शैक्षिक अवसरों में बाधा उत्पन्न करती है। ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अध्ययन में यह पाया गया कि बहुभाषिक शिक्षा विद्यार्थियों की सहभागिता, आत्मविश्वास एवं अधिगम क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। मातृभाषा आधारित शिक्षण विद्यार्थियों को शिक्षा से अधिक प्रभावी रूप से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधनों, तकनीकी अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षकों एवं प्रशासनिक दक्षता की अत्यंत आवश्यकता है। यदि नीति का प्रभावी एवं संतुलित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो यह शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, न्यायसंगत एवं समान अवसर आधारित बनाने का प्रयास करती है। यह नीति सामाजिक समानता, बहुभाषिक शिक्षा एवं समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह नीति सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करती है। यद्यपि नीति के समक्ष संसाधनों की कमी, डिजिटल विभाजन एवं क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है।

अनुशंसाएं

1. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना विकसित की जाए।
2. सामाजिक रूप से वंचित वर्गों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजनाएँ बढ़ाई जाएँ।
3. शिक्षकों को NEP 2020 संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
4. मातृभाषा आधारित शिक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
5. शिक्षा में सामाजिक न्याय एवं समान अवसर सुनिश्चित किए जाएँ।

संदर्भ सूची

- भारत सरकार।)2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। नई दिल्लीशिक्षा मंत्रालय। :
- एनसीईआरटी।)2022). *समावेशी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन*। नई दिल्लीएनसीईआरटी। :
- यूनेस्को।)2021). *शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन रिपोर्ट*। पेरिसयूनेस्को पब्लिशिंग। :

- शर्मा, आर) .2022). भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक समानता। *जर्नल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़*, 12(3), 45–58।
- कुमार, एस) .2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं समावेशी शिक्षा। *इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन*, 8(2), 66–74।
- सिंह, पी) .2023). बहुभाषिक शिक्षा एवं सामाजिक सहभागिता। *एजुकेशनल रिव्यू जर्नल*, 10(1), 22–31।